नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 095
दि. 06.01.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

महायुति में फिलहाल थमी सियासी तलवारें बीजेपी की सख्ती के बाद अजित पवार के बदले सुर

(जीएनएस)। मुंबई। महाराष्ट्र की सियासत में महायुति के भीतर उठे तूफान पर फिलहाल 'युद्धविराम' लगता नजर आ रहा है। पुणे और पिंपरी-चिंचवड नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के बीच बढ़ी तल्ख बयानबाजी के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार ने सोमवार शाम को सार्वजनिक रूप से सफाई देकर माहौल को ठंडा करने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा कि उनके बयान भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नहीं थे, बल्कि स्थानीय निकाय चुनावों के संदर्भ में पुणे और पिंपरी-चिंचवड के कुछ स्थानीय भाजपा नेताओं तक सीमित थे। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है, जब भाजपा की ओर से कड़ी चेतावनी दी गई थी और गठबंधन में दरार की चर्चाएं तेज हो गई थीं।

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से पुणे और पीसीएमसी की सियासत गरमाई हुई थी। अजित पवार ने इन दोनों नगर निगमों में भाजपा के 2017 से 2022 के कार्यकाल पर तीखा हमला बोलते हुए भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने यहां तक कहा था कि भाजपा ने सत्ता की भूख में नगर निगम को कर्ज में डुबो दिया। उनके इन बयानों ने महायुति के भीतर खलबली मचा दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने पलटवार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी थी और यहां तक कह दिया था कि भाजपा ने अजित पवार को साथ लेकर गलती की है। उन्होंने यह चेतावनी भी दी थी कि अगर भाजपा ने जवाबी हमला शुरू किया, तो अजित पवार के लिए

स्थिति मुश्किल हो सकती है। चव्हाण ने दावा किया था कि उन्होंने पहले ही देवेंद्र फडणवीस को इस गठबंधन को लेकर आगाह किया था।

भाजपा की इस सख्त चेतावनी के बाद अजित पवार के तेवर बदले हुए नजर आए। उन्होंने अपने बयान में मीडिया पर भी ठीकरा फोड़ा और कहा कि उनके शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। पवार ने जोर देकर कहा कि उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाया। उलटे उन्होंने मोदी और फडणवीस की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर सरकारें बेहतरीन काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और महाराष्ट्र में शिंदे-फडणवीस सरकार मिलकर विकास योजनाओं को जमीन पर उतार रही है।

अजित पवार ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से विकास कार्यों के लिए फंड की कोई कमी नहीं होने दी जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चाहे वह पुणे हो या पिंपरी-चिंचवड, सभी विकास परियोजनाओं को समय पर धन उपलब्ध कराया जाएगा। उनके इस बयान को भाजपा नेतृत्व को आश्वस्त करने और गठबंधन में आई खटास को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अपने रुख का बचाव करते हुए अजित पवार ने राजनीतिक इतिहास का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है कि केंद्र और राज्य में गठबंधन में रहने वाली पार्टियां स्थानीय निकाय चुनाव अलग-अलग लड़ें। उन्होंने यूपीए सरकार के दौर का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी कांग्रेस और राकांपा साथ सरकार चलाते थे, लेकिन कई बार स्थानीय निकाय चुनावों में एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरते थे। पवार ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और उनका असर राज्य सरकार की स्थिरता या विकास कार्यों पर नहीं पड़ता।

पवार ने मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड में जो सियासी मुकाबला चल रहा है, वह सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित रहेगा। इसका महायुति सरकार या राज्य की विकास यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार का उद्देश्य महाराष्ट्र का विकास है और वह लक्ष्य सभी सहयोगी दलों के लिए समान है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अजित पवार का यह नरम रुख भाजपा की सख्त प्रतिक्रिया और संभावित टकराव के डर का नतीजा है। महायुति के भीतर बढ़ता तनाव अगर और गहराता, तो इसका असर आने वाले चुनावों और सरकार की स्थिरता पर भी पड़ सकता था। फिलहाल अजित पवार की सफाई और मोदी-फडणवीस की खुली तारीफ से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि गठबंधन बरकरार है और मतभेदों को सियासी समझदारी से संभाल लिया गया है। हालांकि, स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान यह 'युद्धविराम' कब तक कायम रहेगा, यह आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा।

बांग्लादेश में नहीं थम रही अल्पसंख्यकों पर हिंसा, एक और हिंदू की गोली मारकर हत्या, महिला के साथ दरिंदगी से बढ़ा तनाव

(जीएनएस)। ढाका। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में एक और हिंदू युवक की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना जाशोर जिले में हुई, जिसने पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। बीते तीन हफ्तों के भीतर हिंदुओं को निशाना बनाकर की गई यह पांचवीं गंभीर घटना बताई जा रही है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय में भय और असुरक्षा की भावना और गहरी हो गई है। जानकारी के अनुसार यह वारदात जाशोर जिले के मणिरामपुर उपजिला के कोपलिया बाजार स्थित वार्ड नंबर 7 में शाम करीब 5 बजकर 45 मिनट पर हुई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय राणा प्रताप के रूप में हुई है, जो केशवपुर उपजिला के अरुआ गांव का निवासी था। उसके पिता का नाम तुषार कांति बैरागी बताया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस सूत्रों के मुताबिक राणा प्रताप बाजार में बैठा हुआ था, तभी कुछ अज्ञात हमलावर अचानक वहां पहुंचे और उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। हमले में राणा के शरीर में कई गोलियां लगीं, जिनमें एक सिर में लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के

बाद हमलावर फरार हो गए। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि राणा प्रताप पेशे से पत्रकार था, हालांकि इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। इस हत्या की खबर फैलते ही इलाके में भारी तनाव फैल गया। स्थानीय हिंदू समुदाय में गुस्सा और डर दोनों साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। इसी बीच, एक और दिल दहला देने वाली घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। झेनैदाह जिले के कालिगंज उपजिला के नादिपारा इलाके में एक 40 वर्षीय हिंदू विधवा महिला के साथ सामूहिक दरिंदगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि इलाके के ही दो स्थानीय बदमाशों ने महिला के साथ पहले बलात्कार किया और इसके बाद उसे पेड़ से बांधकर उसके बाल काट दिए। यही नहीं, आरोपियों ने इस पूरी अमानवीय घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। इस घटना के सामने आने के बाद न केवल हिंदू समुदाय बल्कि पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है।

लगातार हो रही इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा है। इससे पहले भी कई जघन्य घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले दीपू चंद्र दास को एक कपड़ा फैक्ट्री में पीट-पीटकर मार डाला गया था। इसके बाद अमृत मंडल नामक एक अन्य हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। मयमनिंह जिले में हिंदू युवक बृजेंद्र बिस्वास को गोली मार दी गई थी, जबकि खोकन दास की भी भीड़ के हमले में जान चली गई थी। इन सभी मामलों में अब तक न्याय और दोषियों को सख्त सजा मिलने को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

लगातार हो रहे हमलों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया है। मानवाधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर समय रहते इन घटनाओं पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। वहीं, हिंदू समुदाय में यह भावना गहराती जा रही है कि उन्हें सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है।

'निर्विरोध' जीत पर सियासी घमासान, मनसे और कांग्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दी चुनौती

(जीएनएस)। मुंबई। महाराष्ट्र में चल रहे नगर निगम चुनावों के बीच 67 पार्षदों के निर्विरोध चुने जाने का मामला अब गंभीर सियासी विवाद का रूप ले चुका है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह निर्विरोध जीत लोकतांत्रिक सहमति का परिणाम नहीं, बल्कि दबाव, डर और कथित सत्ताधारी दखल का नतीजा है। इसी को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और कांग्रेस पार्टी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज ठाकरे की अगुवाई वाली मनसे ने सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इन निर्विरोध चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं और पूरे मामले की न्यायिक निगरानी में जांच की मांग की है। मनसे नेता अविनाश जाधव की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य में सत्ताधारी गठबंधन ने कई जगहों पर विपक्षी उम्मीदवारों को डराने-धमकाने, दबाव बनाने और पैसे बांटने जैसे हथकंडों का इस्तेमाल किया, जिसके चलते विपक्ष के उम्मीदवारों को मजबूरी में अपने नामांकन वापस लेने पड़े। मनसे का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है और इससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा को गहरा आघात पहुंचा है। पार्टी का आरोप है कि अगर उम्मीदवार भय या दबाव में नाम वापस ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में निर्विरोध चुनाव को लोकतांत्रिक सहमति नहीं कहा जा सकता। विवादित निर्विरोध चुनावों में कल्याण-डोंबिवली, पिंपरी-चिंचवाड़, जलगांव और छत्रपति संभाजीनगर जैसे बड़े शहरी क्षेत्र शामिल हैं, जहां बड़ी संख्या में उम्मीदवार बिना किसी मुकाबले के चुन लिए गए। विपक्ष का दावा है कि इन इलाकों में राजनीतिक दबाव के चलते वास्तविक चुनावी मुकाबला ही नहीं होने दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने भी इसी आधार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि चुनाव प्रक्रिया पर जनता का भरोसा कमजोर होगा, तो इसका सीधा असर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ेगा। चुनाव आयोग से राहत न मिलने के बाद विपक्ष ने इसे आखिरी विकल्प मानते हुए अदालत का रुख किया है।

मनसे की याचिका में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि आयोग की निष्पक्षता संदेह के घेरे में है और उस पर राज्य सरकार का दबाव होने का आरोप लगाया गया है। पार्टी ने हाईकोर्ट से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच कोर्ट की निगरानी में कराई जाए और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन 67 निर्विरोध उम्मीदवारों के परिणाम घोषित न किए जाएं। साथ ही, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए याचिका में त्वरित सुनवाई की भी अपील की गई है, ताकि कथित अनियमितताओं पर शीघ्र फैसला हो सके।

दूसरी ओर, सत्ताधारी पक्ष और महायुति के नेता विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी का काम केवल सवाल उठाना और शोर मचाना रह गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन सीटों पर केवल एक ही उम्मीदवार का नामांकन दाखिल हुआ है, वहां चुनाव आयोग को नियमों के तहत उस उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने का अधिकार है। आठवले ने कहा कि कई स्थानों पर विपक्ष ने खुद ही उम्मीदवार नहीं उतारे या नामांकन दाखिल नहीं किया, ऐसे में निर्विरोध जीत को साजिश बताना उचित नहीं है।

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए निर्विरोध चुनावों को लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत बताया। छत्रपति संभाजीनगर के चिकलथाना हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि निर्विरोध चुनाव जीतना एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है, क्योंकि इससे चुने गए प्रतिनिधि का पूरा ध्यान चुनावी राजनीति की जगह क्षेत्र के विकास पर केंद्रित रहता है। उन्होंने उद्धव ठाकरे की ओर से 68 वार्डों के परिणाम रद्द करने की मांग को भी निराधार बताया और कहा कि यदि विपक्ष को प्रक्रिया पर संदेह है, तो अदालत का दरवाजा खटखटाना उनका अधिकार है।

ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, नौ ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

(जीएनएस)। कोलकाता/मुंबई। ऑनलाइन सट्टेबाजी और अवैध गेमिंग नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए देश के कई शहरों में एक साथ छापेमारी की। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत ईडी के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय की अगुवाई में दिल्ली, मुंबई, सूरत, लखनऊ और वाराणसी समेत कुल नौ ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के साथ-साथ कई ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी एप्लिकेशनों से जुड़े लोगों के खिलाफ की गई है।

ईडी सूत्रों के मुताबिक, तलाशी के दौरान अनुराग द्विवेदी की दो महंगी लग्जरी कारें—लैंड रोवर डिफेंडर और बीएमडब्ल्यू Z4—जब्त की गई हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन, लैपटॉप और वित्तीय लेनदेन से जुड़े अहम सबूत भी हाथ लगे हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

जांच में यह भी सामने आया है कि अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से अर्जित 'अपराध की आय' (Proceeds of Crime) को हवाला चैनलों के माध्यम से भारत से बाहर भेजा गया। ईडी का दावा है कि यह पैसा दुबई पहुंचाया गया, जहां इसका इस्तेमाल रियल एस्टेट और अन्य अचल संपत्तियों में निवेश के लिए किया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क का उद्देश्य सट्टेबाजी से कमाए गए काले धन को वैध दिखाना और विदेशों में संपत्ति खड़ी करना था।

इससे पहले 17 दिसंबर को हुई छापेमारी में भी ईडी ने इसी मामले में चार लग्जरी गाड़ियां—जिनमें लेम्बोर्गिनी उरुस और मर्सिडीज जैसी महंगी कारें शामिल थीं—जब्त की थीं। उस दौरान करीब 20 लाख रुपये नकद भी बरामद किए गए थे। अब तक ईडी लगभग 3 करोड़ रुपये की चल संपत्तियों को फ्रीज कर चुकी है, जिनमें बीमा पॉलिसी, फिक्स्ड डिपॉजिट और विभिन्न बैंक खातों में जमा रकम शामिल है।

ईडी की यह जांच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज नाम के आरोपी सिलीगुड़ी से इस अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क का संचालन कर रहे थे। ये लोग फर्जी बैंक खातों, डमी कंपनियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी के पैनल चला रहे थे।

ईडी के अनुसार, अनुराग द्विवेदी ने इन अवैध सट्टेबाजी और गेमिंग एप्स का सोशल मीडिया के जरिए प्रचार-प्रसार किया। इसके बदले में उन्हें मोटी रकम दी जाती थी, जिसे बिचौलियों और फर्जी खातों के माध्यम से घुमाकर वैध दिखाने की कोशिश की गई। जांच एजेंसी का आरोप है कि द्विवेदी न सिर्फ प्रमोशन में शामिल थे, बल्कि सट्टेबाजी से आए पैसों की लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे।

ईडी अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। डिजिटल सबूतों और बैंकिंग ट्रांजैक्शनों की गहन पड़ताल की जा रही है। एजेंसी को आशंका है कि इस नेटवर्क के तार देश के अन्य हिस्सों और विदेशों तक फैले हो सकते हैं।

इस कार्रवाई को ऑनलाइन सट्टेबाजी और सोशल मीडिया के जरिए हो रहे अवैध वित्तीय लेनदेन पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है।

जजों की सुरक्षा पर 'सुप्रीम' संदेश, निडर न्यायाधीश ही स्वतंत्र न्यायपालिका की असली ताकत

(जीएनएस)। नई दिल्ली। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निचली अदालतों के न्यायाधीशों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम, कड़ा और दूरगामी संदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि केवल किसी आदेश के गलत होने, निर्णय में कथित चूक या विवेकाधिकार के प्रयोग के आधार पर किसी न्यायिक अधिकारी को विभागीय कार्रवाई, निलंबन या आपराधिक मुकदमे की पीड़ा नहीं झेलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर न्यायाधीश डर के माहौल में काम करेंगे तो न्याय व्यवस्था की नींव ही कमजोर हो जाएगी। यह ऐतिहासिक टिप्पणी मध्य प्रदेश के एक जिला न्यायाधीश की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए की गई है। मामला मध्य प्रदेश कैडर के जिला न्यायाधीश निर्भय सिंह सुलिया से जुड़ा है, जिन्हें आबकारी अधिनियम से जुड़े मामलों में जमानत देते समय अलग-अलग मानक अपनाने और कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर सेवा से हटा दिया गया था। राज्य सरकार ने यह कार्रवाई हाईकोर्ट की सिफारिश पर की थी। दरअसल, निर्भय सिंह सुलिया पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने आबकारी मामलों में जमानत देते समय एक समान पैमाने का पालन नहीं किया और कुछ मामलों में अनुचित तरीके से जमानत मंजूर की। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में यह मान लिया था कि जमानत आदेशों में भ्रष्टाचार के तत्व मौजूद हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने सुलिया को बर्खास्त करने की सिफारिश की और राज्य सरकार ने उसे मंजूरी दे दी।

इस फैसले के खिलाफ निर्भय सिंह सुलिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मामले की सुनवाई जस्टिस जे.बी. परदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने न केवल सुलिया की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया, बल्कि पूरे देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए एक स्पष्ट दिशा-निर्देश भी दे दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि न्यायिक अधिकारी का मूल काम कानून के अनुसार फैसले देना है। हर फैसले में एक पक्ष को संतोष होता है और दूसरा पक्ष असंतुष्ट रहता है। यह असंतुष्ट पक्ष कई बार बदले की भावना से न्यायाधीश के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोप भी लगा सकता है। अगर हर ऐसे आरोप को आधार बनाकर न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ विभागीय या आपराधिक कार्रवाई शुरू कर दी जाए, तो कोई भी जज स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर फैसला नहीं दे पाएगा।

अदालत ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि "डर के साये में काम करने वाला न्यायाधीश न्याय नहीं कर सकता।" सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत देना या न देना न्यायिक विवेक का विषय है। अगर हर जमानत आदेश को बाद में जांच के दायरे में लाकर भ्रष्टाचार से जोड़ दिया जाएगा, तो निचली अदालतों के जज जोखिम लेने से बचेंगे और इससे न्याय में देरी तथा अन्याय की स्थिति पैदा होगी।

पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि न्यायिक अधिकारियों को गलत फैसलों के लिए अपील और पुनरीक्षण जैसी वैधानिक प्रक्रियाओं के जरिए सुधारा जा सकता है, न कि अनुशासनात्मक कार्रवाई या बर्खास्तगी जैसे कठोर कदम उठाकर। अदालत ने कहा कि जब तक किसी जज के खिलाफ रिश्वत लेने या स्पष्ट आपराधिक कृत्य का ठोस और निर्विवाद सबूत न हो, तब तक उनके फैसलों को आधार बनाकर उन्हें दंडित करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

अमेरिकी निरंकुशता वैश्विक कानूनों का अतिक्रमण

पिछले लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर रहे वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सैन्य हमले के बाद गिरफ्तार किया जाना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में एक अत्यंत गंभीर और खतरनाक मोड़ के रूप में देखा जाना चाहिए। किसी संप्रभु राष्ट्र पर सैन्य आक्रमण कर उसके निर्वाचित राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अपने देश ले जाना न केवल संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है, बल्कि यह उस वैश्विक व्यवस्था की बुनियाद को भी हिलाता है, जिसकी बात अमेरिका स्वयं दशकों से करता आया है। इससे भी अधिक चिंताजनक ट्रंप का यह ऐलान है कि सत्ता परिवर्तन होने तक वेनेज़ुएला का संचालन वाशिंगटन से किया जाएगा। यह घोषणा वस्तुतः औपनिवेशिक मानसिकता का आधुनिक संस्करण है, जिसमें किसी देश की जनता की इच्छा, उसकी संप्रभुता और उसकी ऐतिहासिक-सांस्कृतिक पहचान को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। वेनेज़ुएला में मादुरो के पतन के बाद की प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से मिश्रित होगी। यह सच है कि मादुरो के शासनकाल में देश गंभीर आर्थिक संकट से गुज़रा, महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी, राजनीतिक असहमति को कठोरता से दबाया गया और लाखों नागरिक बेहतर जीवन की तलाश में देश छोड़ने को मजबूर हुए। चुनावी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते रहे और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे आरोप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार-बार दोहराए गए। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि मादुरो को एक वैश्विक खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने में केवल आंतरिक विफलताएं ही नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय अभियान भी सक्रिय था। इस अभियान का उद्देश्य लोकतंत्र या मानवाधिकारों की रक्षा से अधिक वेनेज़ुएला की रणनीतिक और आर्थिक अहमियत को ध्यान में रखते हुए सत्ता संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ना रहा है। वैश्विक कूटनीति के जानकारों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन का यह कदम तानाशाही के कथित पीड़ितों को न्याय दिलाने या वेनेज़ुएला की जनता को राहत पहुंचाने के नाम पर उठाया गया कदम कम और देश के विशाल तेल भंडारों पर नियंत्रण स्थापित करने की रणनीति अधिक है। वेनेज़ुएला दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडारों में से एक का मालिक है और ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण आज भी वैश्विक राजनीति की धुरी बना हुआ है। ऐसे में यह विश्वास करना कठिन नहीं कि मादुरो की गिरफ्तारी और सत्ता परिवर्तन की आड़ में असली लड़ाई तेल, गैस और भू-रणनीतिक प्रभाव की है। ट्रंप द्वारा यह कहना कि इस सैन्य अभियान का खर्च वेनेज़ुएला के तेल राजस्व से वसूला जाएगा, इस मंशा को और भी स्पष्ट कर देता है। यह कथन किसी भी संप्रभु देश के प्राकृतिक संसाधनों पर खुलेआम अधिकार जताने जैसा है। अमेरिका द्वारा सैन्य बल के प्रयोग से किसी देश के शासनाध्यक्ष को हटाना और वहां की सत्ता को अपने नियंत्रण में लेना साम्राज्यवादी सोच का ही प्रतीक है। यह वही सोच है जिसने अतीत में इराक और अफगानिस्तान जैसे देशों को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। इन दोनों ही देशों में भी अमेरिका ने लोकतंत्र, सुरक्षा और स्थिरता के नाम पर सैन्य हस्तक्षेप किया था। शुरुआती दौर में शक्ति प्रदर्शन और आत्मविश्वास का माहौल था, लेकिन वर्षों बाद इन अभियानों का अंत अव्यवस्था, हिंसा और अपमानजनक वापसी के रूप में हुआ। सबसे दुखद तथ्य यह है कि इन देशों की जनता आज भी सामान्य जीवन की तलाश में संघर्ष कर रही है। शासन बदलना आसान साबित हुआ, लेकिन शांति, स्थिरता और संस्थागत निर्माण की प्रक्रिया कहीं अधिक जटिल और लंबी निकली। वेनेज़ुएला के मामले में भी यही खतरा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ट्रंप प्रशासन ने यह तो कह दिया कि सत्ता परिवर्तन तक देश का संचालन वाशिंगटन करेगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि इसके बाद किस नेता या किस राजनीतिक व्यवस्था को सत्ता सौंपी जाएगी। क्या वह नेता वास्तव में वेनेज़ुएला की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेगा या वह केवल अमेरिकी हितों का संरक्षक होगा? यह अनिश्चितता देश को लंबे समय तक अस्थिरता और आंतरिक संघर्ष की ओर धकेल सकती है। सत्ता के इस शून्य में विभिन्न गुटों, सैन्य धड़ों और बाहरी शक्तियों के बीच टकराव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इस अमेरिकी कार्रवाई के गहरे भू-राजनीतिक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। यहां तक कि वे देश भी, जो पहले मादुरो के कट्टर आलोचक रहे हैं और अमेरिका के सहयोगी माने जाते हैं, अब खुलकर चेतावनी देने लगे हैं। उन्हें डर है कि अगर आज यह वेनेज़ुएला के साथ हो सकता है, तो कल किसी और देश की बारी भी आ सकती है। रूस और चीन ने इस कदम को नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधा खतरा बताया है। उनका तर्क है कि अगर शक्तिशाली देश अपनी सुविधा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करेंगे, तो वैश्विक अराजकता को रोकना असंभव हो जाएगा। चीन के लिए यह घटनाक्रम विशेष रूप से उपयोगी साबित हो रहा है, क्योंकि इससे उसे अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर होने वाली अमेरिकी आलोचना को कमजोर करने का अवसर मिला है।

सोमनाथ : आस्था के हजार वर्ष, आशा का अनंत नाद

> "अतीत के आक्रमणकारी आज समय की धूल बन चुके हैं। उनका नाम अब विनाश के प्रतीक के तौर पर लिया जाता है। इतिहास के पन्नों में वे केवल फुटनोट हैं, जबकि सोमनाथ आज भी अपनी आशा बिखेरता हुआ प्रकाशमान खड़ा है। सोमनाथ हमें ये बताता है कि घृणा और कट्टरता में विनाश की विकृत ताकत हो सकती है, लेकिन आस्था में सृजन की शक्ति होती है।

सोमनाथ, ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में, प्रभास पाटन नाम की जगह पर स्थित सोमनाथ, भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतीकरण है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम् में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। ज्योतिर्लिंगों का वर्णन इस पंक्ति से शुरू होता है... 'सौराष्ट्रे सोमनाथं च...' यानी ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का उल्लेख आता है। ये इस पवित्र धाम की सभ्यतागत और आध्यात्मिक महत्ता का प्रतीक है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है :- लभते फलं मनोवाञ्छितं मृतः स्वर्गं समाश्रयेत्॥'

अर्थात, सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मन में जो भी पुण्य कामनाएं होती हैं, पूरी होती हैं व मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग को प्राप्त होती है। दुर्भाग्यवश, यही सोमनाथ जो करोड़ों लोगों की श्रद्धा व प्रार्थनाओं का केंद्र था, विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना, जिनका उद्देश्य विध्वंस था।

वर्ष 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि इस महान तीर्थ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनवरी 1026 में गजनी के महमूद ने इस मंदिर पर बड़ा आक्रमण किया था, यह मंदिर ध्वस्त कर दिया था। यह आक्रमण आस्था और सभ्यता के एक महान प्रतीक को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया एक हिंसक और बर्बर प्रयास था।

सोमनाथ हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल है। फिर भी, एक हजार वर्ष बाद आज भी यह मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। साल 1026 के बाद समय-समय पर इस मंदिर को उसके पूरे वैभव के साथ पुनःनिर्मित करने के प्रयास जारी रहे। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में आकार ले सका। संयोग से 2026 का यही वर्ष सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का भी वर्ष है। 11 मई 1951 को इस मंदिर का पुनर्निर्माण सम्पन्न हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में हुआ वो समारोह ऐतिहासिक था, जब मंदिर के द्वार

दर्शनों के लिए खोले गए थे।

1026 में एक हजार वर्ष पहले सोमनाथ पर पहले आक्रमण, लोगों से क्रूरता व विध्वंस का वर्णन कई ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है। हर पंक्ति में क्रूरता के निशान मिलते हैं, ये ऐसा दुःख है जिसकी पीड़ा लगातार महसूस होती है। कल्पना कर सकते हैं कि इसका उस दौर में भारत पर व लोगों के मनोबल पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा। सोमनाथ मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत था। ये ऐसे समाज की प्रेरणा था जिसकी आर्थिक क्षमता भी बहुत सशक्त थी। हमारे समुद्री व्यापारी और नाविक इसके वैभव की कथाएं दूर-दूर तक ले जाते थे।

सोमनाथ पर हमले और फिर गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद आज मैं पूरे विश्वास व गर्व से कहना चाहता हूं कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं। ये 1000 साल से चली आ रही भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है, भारत के लोगों की अटूट आस्था की गाथा है। 1026 में शुरू हुई मध्यकालीन बर्बरता ने आगे चलकर दूसरों को भी बार-बार सोमनाथ पर आक्रमण के लिए उकसाया। यह लोगों व हमारी संस्कृति को गुलाम बनाने का प्रयास था। लेकिन हर बार जब मंदिर पर हमला हुआ, तब हमारे पास ऐसे महान पुरुष और महिलाएं भी थीं जिन्होंने उसकी रक्षा के लिए खड़े होकर सर्वोच्च बलिदान दिया। हर बार, पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारी महान सभ्यता के लोगों ने खुद को संभाला, मंदिर को पुनः जीवंत किया।

गजनवी लूटकर चला गया, लेकिन सोमनाथ के प्रति हमारी भावना को हमसे छीन नहीं सका। सोमनाथ से जुड़ी हमारी आस्था, विश्वास और प्रबल हुआ। उसकी आत्मा लाखों श्रद्धालुओं के भीतर सांस लेती रही। साल 1026 के हजार साल बाद आज 2026 में भी सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है- मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, जबकि सोमनाथ मंदिर हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है।

सौभाग्य है कि हमने उस धरती पर जीवन पाया है, जिसने देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी महान विभूति को जन्म दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने का पुण्य प्रयास किया कि श्रद्धालु सोमनाथ में पूजा कर सकें। 1890 के दशक में स्वामी विवेकानंद भी सोमनाथ आए थे, वो अनुभव उन्हें भीतर तक आंदोलित कर गया। 1897 में चेन्नई में दिए व्याख्यान में उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की। उन्होंने कहा, 'दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर और गुजरात के सोमनाथ जैसे मंदिर आपको ज्ञान के अनगिनत पाठ सिखाएंगे। ये आपको किसी भी संख्या में पढ़ी गई पुस्तकों से अधिक हमारी सभ्यता की गहरी समझ देंगे।

इन मंदिरों पर सैकड़ों आक्रमणों के निशान हैं, और सैकड़ों बार इनका पुनर्निर्माण हुआ है। ये बार बार नष्ट किए गए, और हर बार अपने ही खंडहरों से फिर खड़े हुए। पहले की तरह सशक्त व जीवंत। यही राष्ट्रीय मन है, राष्ट्रीय जीवनधारा है। इसका अनुसरण आपको गौरव से भर देता है। इसको छोड़ देने का मतलब है, मृत्यु।' आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार वल्लभभाई पटेल के सक्षम हाथों में आया। 1947 में दिवाली के समय उनकी सोमनाथ यात्रा हुई। उस अनुभव ने उन्हें भीतर तक झकझोरा, उन्होंने तत्काल घोषणा की कि यहीं सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। अंततः 11 मई, 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। उस मौके पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। महान सरदार साहब यह ऐतिहासिक दिन देखने को जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपना राष्ट्र के सामने साकार होकर भव्य रूप में उपस्थित था।

तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बनें। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी। लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे, और फिर जो हुआ, उसने एक नया इतिहास रच दिया।

सोमनाथ मंदिर का कोई भी उल्लेख के.एम. मुंशी जी के योगदानों को याद किए बिना अधूरा है। उन्होंने उस समय सरदार पटेल का प्रभावी रूप से समर्थन किया। सोमनाथ पर उनका कार्य, विशेषतया उनकी पुस्तक 'सोमनाथ, द श्राइन इटरनल', अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। निःसंदेह, हम एक ऐसी सभ्यता हैं जो आत्मा और विचारों की अमरता में अटूट विश्वास रखती है। हम विश्वास करते हैं—नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। सोमनाथ का भौतिक ढांचा नष्ट हो गया, लेकिन उसकी चेतना अमर रही।

इन्हीं विचारों ने हमें हर कालखंड में, हर परिस्थिति में फिर से उठ खड़े होने, मजबूत बनने और आगे बढ़ने का सामर्थ्य दिया है। इन्हीं मूल्यों और हमारे लोगों के संकल्प की वजह से आज भारत पर दुनिया की नजर है। दुनिया हमारे इनोवेटिव युवाओं में निवेश करना चाहती है। हमारी कला, संस्कृति, हमारा संगीत और हमारे अनेक पर्व आज वैश्विक पहचान बना रहे हैं। स्वस्थ जीवन के लिए योग और आयुर्वेद जैसे विषय पूरी दुनिया में प्रभाव डाल रहे। अनादि काल से सोमनाथ जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ता आया है। सदियों पहले जैन परंपरा के आदरणीय मुनि कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य यहां आए थे और कहा जाता है कि प्रार्थना के बाद उन्होंने कहा, 'भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याः क्षयमुपगता यस्य।' अर्थात्, उस परम तत्व को नमन जिसमें सांसारिक बंधनों के बीज नष्ट हो चुके हैं। जिसमें राग और सभी विकार शांत हो गए हैं।

आज भी दादा सोमनाथ के दर्शन से ऐसी ही अनुभूति होती है। मन में एक ठहराव आ जाता है, आत्मा को अंदर तक कुछ स्पर्श करता है, जो अलौकिक है, अव्यक्त है। 1026 के पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष बाद 2026 में भी सोमनाथ का समुद्र उसी तीव्रता से गर्जना करता है व तट स्पर्श करती लहरें उसकी पूरी गाथा सुनाती हैं। उन लहरों की तरह सोमनाथ बार-बार उठता रहा। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ आज भी आशा का अनंत नाद है। विश्वास का वो स्वर, जो टूटने के बाद भी उठने की प्रेरणा देता है। अगर हजार साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम हजार साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। आइए, इसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक नए संकल्प के साथ, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए। एक ऐसा भारत, जिसका सभ्यतागत ज्ञान हमें विश्व कल्याण के लिए प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है।

प्रेरणा

देने में जो सुख है, वह पाने में कहाँ

अमेरिकी प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानन्द का जीवन केवल विचारों और ओजस्वी भाषणों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका प्रत्येक दिन मानवीय संवेदना, सेवा और त्याग का सजीव उदाहरण था। विश्व धर्म महासभा में भारत का नाम रोशन करने के बाद वे अमेरिका के विभिन्न नगरों में आमंत्रित किए जाते थे। कहीं प्रवचन, कहीं संवाद, तो कहीं निजी चर्चाएँ—उनका जीवन अत्यंत व्यस्त था। इसके बावजूद उनका निजी जीवन अत्यंत सरल था। वे सादगी में विश्वास रखते थे और अपने दैनिक कार्य स्वयं करते थे। उन दिनों वे अपने हाथों से भोजन बनाते थे, क्योंकि उनके लिए आत्मनिर्भरता केवल व्यवहार नहीं, बल्कि एक साधना थी।

एक दिन, लगातार यात्राओं और भाषणों की थकान के बाद वे अपने निवास स्थान पर लौटे। उन्होंने साधारण भोजन तैयार किया और भोजन करने की तैयारी ही कर रहे थे कि कुछ छोटे बच्चे उनके पास आकर खड़े हो गए। बच्चों के चेहरे पर भूख साफ झलक रही थी। आँखों में मासूम अपेक्षा थी और शरीर की दुर्बलता उनकी स्थिति को बयान कर रही थी। स्वामी विवेकानन्द का व्यक्तित्व बच्चों को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता था। उनके चेहरे पर कठोरता नहीं, बल्कि वात्सल्य और अपनापन था। इसी कारण बच्चे बिना किसी भय के उनके पास आ जाते थे, मानो वे उन्हें अपना ही कोई समझते हों।

स्वामी जी ने उन बच्चों को देखा और एक क्षण भी नहीं सोचा। उन्होंने अपना सारा भोजन बच्चों में बाँट दिया। न कोई हिसाब, न कोई झिझक और न ही भविष्य की चिंता। उनके लिए उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सामने खड़े बच्चों की भूख शांत हो जाए। वहीं पास में बैठी एक महिला यह दृश्य देख रही थी। वह इस त्याग को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने सहज भाव से प्रश्न किया कि आपने अपना पूरा भोजन बच्चों को दे दिया, अब आप क्या खाएंगे। यह प्रश्न उस सामान्य सोच का प्रतिनिधित्व करता था, जिसमें पहले स्वयं की आवश्यकता को प्राथमिकता देना स्वाभाविक माना जाता है।

स्वामी विवेकानन्द ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि रोटी तो केवल पेट की आग बुझाने का साधन है। यदि इस पेट में न सही, तो उनके पेट में ही सही। आखिर ये सब भी तो भगवान के ही अंश हैं। देने का आनंद पाने के आनंद से कहीं बड़ा है। इस उत्तर में केवल करुणा ही नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का गहरा दर्शन छिपा हुआ था। उनके लिए ईश्वर किसी मंदिर या मूर्ति में सीमित नहीं था, बल्कि प्रत्येक भूखे, दुखी और पीड़ित मानव में विद्यमान था। जब उन्होंने बच्चों को भोजन दिया, तो वह उनके लिए ईश्वर की ही सेवा थी। यह घटना आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। आधुनिक समाज में सफलता और सुख का माप अक्सर संग्रह, उपभोग और प्रतिस्पर्धा से किया जाता है। हम जितना अधिक पाते हैं, उतना ही स्वयं को सुरक्षित और सुखी मानते हैं। लेकिन यह सुख अस्थायी होता है। पाने की लालसा कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि और तीव्र हो जाती है। इसके विपरीत, देने का आनंद शांति देता है। वह मन को हल्का करता है और आत्मा को तृप्त करता है। स्वामी विवेकानन्द का जीवन इस सत्य का प्रमाण था कि सच्चा सुख त्याग और सेवा में ही निहित है।

देने का अर्थ केवल धन या भोजन देना नहीं है। इसका अर्थ है अपना समय देना, अपनी संवेदना देना, अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करना। जब हम किसी की पीड़ा को समझते हैं और उसे कम करने का प्रयास करते हैं, तब हम केवल दूसरे का नहीं, बल्कि अपना भी कल्याण करते हैं। स्वामी विवेकानन्द ने अपने आचरण से यह दिखाया कि अध्यात्म का वास्तविक स्वरूप कर्म में प्रकट होता है। केवल उपदेश देने से समाज नहीं बदलता, बल्कि उदाहरण प्रस्तुत करने से परिवर्तन आता है।

उन बच्चों के लिए वह भोजन केवल कुछ रोटियां नहीं थीं। वह विश्वास था कि इस दुनिया में करुणा अभी जीवित है। वह अनुभूति थी कि कोई है, जो बिना किसी स्वार्थ के उनकी परवाह करता है। ऐसे अनुभव किसी भी बाल मन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं और उसे मानवता में विश्वास करना सिखाते हैं। वहीं उस महिला के लिए भी यह दृश्य एक गहरी सीख रहा होगा। संभव है कि उसने पहली बार यह अनुभव किया हो कि महानता त्याग में होती है, संग्रह में नहीं। स्वामी विवेकानन्द का मानना था कि भूखे को भोजन देना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा था कि जब तक एक भी व्यक्ति भूखा है, तब तक किसी भी समाज का स्वयं को सभ्य कहना खोखला है। उनके विचार केवल दार्शनिक नहीं थे, बल्कि व्यावहारिक थे। उन्होंने अपने जीवन में बार-बार यह सिद्ध किया कि मानव सेवा और ईश्वर सेवा में कोई अंतर नहीं है। यही कारण है कि वे केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में आज भी आदर और प्रेरणा के स्रोत हैं।

आज जब समाज में संवेदनशीलता कम होती जा रही है, जब मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना उलझ गया है कि उसे सामने वाले की पीड़ा दिखाई नहीं देती, तब "देने का आनंद" जैसी घटनाएँ हमें आईना दिखाती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि मनुष्य होने का अर्थ केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। जब हम किसी जरूरतमंद के जीवन में थोड़ी सी भी राहत ला पाते हैं, तब हमारा जीवन सार्थक होता है।

पाने का आनंद क्षणिक होता है। वह क्षण भर के लिए सुख देता है, फिर खालीपन छोड़ जाता है। इसके विपरीत, देने का आनंद स्थायी होता है। वह मन को शांति देता है, अहंकार को गलाता है और मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। स्वामी विवेकानन्द का यह संदेश आज भी उतना ही जीवंत है जितना उस दिन था। यदि हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी त्याग और करुणा को स्थान दे दें, तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन, बल्कि पूरा समाज अधिक मानवीय और सुंदर बन सकता है। यही करुणा का उत्सव है, यही देने का सच्चा आनंद।

दुनियाभर में अपना लट्ठ गाड़ने पर क्यों तुले हैं 'चौधरी' ट्रंप? Latin America के देशों में क्यों मची है खलबली?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि क्यूबा आर्थिक रूप से टूटने के कगार पर है, ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और अगर ईरान में सरकार ने जनता पर दमन तेज किया तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। यही नहीं वेनेज़ुएला की राजधानी पर अमेरिकी हमले को लेकर उन्होंने खुले तौर पर कहा कि हम ही प्रभारी हैं और यह अभियान शांति के लिए था। कोलंबिया को भी ट्रंप ने चेतावनी दी है और भारत को भी रूसी तेल खरीदने पर शुल्क बढ़ाने की धमकी दी है। देखा जाये तो ट्रंप के इन बयानों और कार्रवाइयों ने अमेरिका की आक्रामक विदेश नीति को फिर उजागर कर दिया है। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र में भी वेनेज़ुएला पर अमेरिकी कार्रवाई की वैधता पर बहस तेज हो गई है और दुनिया एक बार फिर दो ध्रुवों में बंटती दिख रही है। अमेरिका यह दावा कर रहा है कि उसने अपराधी को पकड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि अपराध तय करने का अधिकार किसने दिया। क्या दुनिया में केवल एक ही देश न्यायाधीश है। क्या लोकतंत्र की परिभाषा अब बंदूक की नली से तय होगी। अगर यही नियम है, तो कल किसी और देश की बारी भी आ सकती है। यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। जहां ताकतवर देश खुलेआम कमजोर देशों की सरकारें गिराने लगे हैं। आज मादुरो जेल में है। कल कोई और होगा। सवाल यह नहीं कि मादुरो सही था या गलत। सवाल यह है कि क्या दुनिया अब बंदूक के कानून से चलेगी। अगर इसका जवाब हां है, तो यह केवल वेनेज़ुएला की हार नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था की हार होगी।

यह भी साफ दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति अब धमकी की भाषा बोल रही है। वह हर मंच से खुद को शांति दूत बताने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके कदम लगातार युद्ध और हस्तक्षेप की ओर बढ़ते दिखते हैं। क्यूबा, कोलंबिया और ग्रीनलैंड को लेकर उनकी ताजा धमकियां उस सोच का हिस्सा हैं जिसमें अमेरिका खुद को पूरी दुनिया का निर्णायक मानता है। क्यूबा पर ट्रंप का बयान यह दिखाता है कि अमेरिका अब भी शीत युद्ध की मानसिकता से बाहर नहीं आया है। क्यूबा को कमजोर बताकर वह यह संकेत देना चाहते हैं कि वेनेज़ुएला से उसका आर्थिक सहारा टूट चुका है और अब दबाव डालने का सही समय है। अमेरिका के लिए क्यूबा सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि वैचारिक चुनौती रहा है। अगर अमेरिका क्यूबा पर सीधे हमले की कोशिश करता है तो यह लैटिन अमेरिका में भारी अस्थिरता ला सकता है। इससे अमेरिका विरोधी भावनाएं और तेज होंगी और रूस तथा चीन को दखल का नया मौका मिलेगा। वहीं, ट्रंप का कोलंबिया को धमकी देना बताता है कि अमेरिका अब अपने पुराने सहयोगियों को भी नहीं बख्श रहा। वेनेज़ुएला प्रकरण के बाद लैटिन अमेरिका में हालात पहले ही तनावपूर्ण हैं। कई देश अमेरिकी दबाव से थक चुके हैं। वेनेज़ुएला पर हमले को क्षेत्र के कई देशों ने संप्रभुता पर हमला माना है। अमेरिका पहले भी चिली, निकारागुआ और पनामा जैसे देशों में दखल देता रहा है। कभी तख्तापलट के जरिए तो कभी आर्थिक प्रतिबंधों से। आज भी वही नीति नए शब्दों में लौट आई है।

दूसरी ओर, ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का बयान दरअसल आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दिखाता है। ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए सामरिक दृष्टि से अहम है। यहां से रूस और चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। लेकिन किसी क्षेत्र को जरूरत बताकर हथियाने की सोच उपनिवेशवादी मानसिकता का उदाहरण है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर दबाव बढ़ाता है तो यह यूरोप और नाटो के भीतर भी दरार पैदा कर सकता है।

वहीं ईरान को लेकर ट्रंप की चेतावनी यह दिखाती है कि अमेरिका खुद को विश्व का पुलिसमैन मानता है। ईरान के आंतरिक मामलों में इस तरह की धमकी अंतरराष्ट्रीय कानून की अवहेलना है। यह संदेश दिया जा रहा है कि जो भी सरकार अमेरिका की लाइन से हटेगी उसे बल प्रयोग से सुधारा जाएगा। इससे पश्चिम एशिया में पहले से जारी तनाव और भड़क सकता है।

उधर, भारत के साथ अमेरिका के रणनीतिक संबंधों के बावजूद ट्रंप की धमकियां बताती हैं कि उनकी दोस्ती भी शर्तों पर टिकी है। भारत को रूसी तेल खरीदने पर चेतावनी देकर वह यह साबित करना चाहते हैं कि अमेरिकी हित सर्वोपरि हैं। यह दबाव नीति भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को चुनौती देती है और बताती है कि अमेरिका साझेदारी को बराबरी का नहीं बल्कि नियंत्रण का जरिया मानता है।

हम आपको यह भी बता दें कि वेनेज़ुएला पर अमेरिकी हमले को दुनिया ने अलग-अलग नजर से देखा है। वेनेज़ुएला का कहना है कि यह सीधी आक्रामकता है जबकि अमेरिका इसे शांति अभियान बता रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में इस कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठे हैं। कई देशों ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा है। इस हमले ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ अमेरिका और उसके समर्थक हैं तो दूसरी तरफ वह देश हैं जो संप्रभुता और बहुपक्षीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं।

इसके अलावा, वेनेज़ुएला के बाद लैटिन अमेरिका में अमेरिका विरोधी भावना और मजबूत हुई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका आज भी मोनरो सिद्धांत के नाम पर पूरे महाद्वीप को अपना हिस्सा मानता है। ट्रंप ने खुद कहा कि यह हमारा गोलार्ध है। यह बयान साफ करता है कि अमेरिका अब भी क्षेत्रीय वर्चस्व की पुरानी सोच से बाहर नहीं निकला है।

यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो नेता रोज शांति की बात करता है और नोबेल शांति पुरस्कार पर अपना दावा करता है वही युद्ध क्यों छेड़ता जा रहा है? इसका जवाब ट्रंप की घरेलू राजनीति में छिपा है। दरअसल आक्रामक राष्ट्रवाद उनके समर्थकों को जोश देता है। हर नया टकराव उन्हें मजबूत नेता के रूप में पेश करता है। शांति उनके लिए लक्ष्य नहीं बल्कि नारा है।

अभियान

जिस मार्ग से माता कुंती पहुँचीं मोक्ष तक - एक आध्यात्मिक गाथा

महाभारत की विराट गाथा में यदि किसी स्त्री पात्र ने मौन त्याग, असाधारण धैर्य और धर्मनिष्ठा के साथ जीवन जिया, तो वह थीं माता कुंती। उन्हें प्रायः पांडवों की माता के रूप में ही स्मरण किया जाता है, किंतु उनका व्यक्तित्व इससे कहीं अधिक व्यापक, गूढ़ और आध्यात्मिक था। कुंती केवल एक राजमाता नहीं थीं, बल्कि वे उस चेतना का प्रतीक थीं जो जीवन के प्रत्येक चरण में कर्तव्य को भावनाओं से ऊपर रखती है। उनका संपूर्ण जीवन संघर्ष, आत्मसंयम और अंततः वैराग्य की ऐसी मिसाल है, जो आज भी मनुष्य को मोह से ऊपर उठकर सत्य और मोक्ष के मार्ग की प्रेरणा देती है।

बहुत कम लोग जानते हैं कि माता कुंती का जन्म साधारण नहीं था। उनका वास्तविक नाम पृथा था और वे यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री थीं। बाल्यावस्था में ही उन्हें कुंतीभोज ने गोद ले लिया, जिसके कारण वे कुंती कहलाईं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंती कोई साधारण स्त्री नहीं थीं, बल्कि वे एक दिव्य शक्ति का अंश थीं। महाभारत और कुछ पुराणों में उन्हें 'सिद्धि' का अवतार माना गया है। सिद्धि को सफलता, सामर्थ्य और आध्यात्मिक पूर्णता की देवी कहा जाता है। वहीं कुछ ग्रंथों में कुंती को 'मति', अर्थात् दिव्य बुद्धि का अवतार भी बताया गया है। यही कारण था कि उनके निर्णयों में असाधारण विवेक और उनकी सहनशीलता में अलौकिक स्थिरता दिखाई देती है।

कुंती के पूर्व जन्म और दैवीय अंश के कारण ही उनके भीतर ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र को सिद्ध करने की अद्भुत क्षमता थी। यह मंत्र कोई साधारण वरदान नहीं था, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति थी जिसके माध्यम से देवताओं का आह्वान किया जा सकता था। इसी मंत्र के प्रभाव से कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया और कर्ण का जन्म हुआ। बाद में धर्मराज यम से युधिष्ठिर, पवनदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन जैसे तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। यहां यह समझना आवश्यक है कि कुंती के लिए मातृत्व केवल जैविक संबंध नहीं था, बल्कि यह एक दायित्व था जिसे उन्होंने आजीवन धर्म के साथ निभाया।

पांडवों के जीवन का अधिकांश भाग संघर्ष में बीता और उस संघर्ष की मूक साक्षी तथा सहयात्री माता कुंती ही थीं। वनवास, अपमान, द्रौपदी चीरहरण का दुःख, पुत्रों पर मंडराता मृत्यु का साया—इन सबको कुंती ने भीतर ही भीतर सहा, लेकिन कभी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुईं। उन्होंने अपने पुत्रों को कभी प्रतिशोध के अंधे मार्ग पर नहीं जाने दिया, बल्कि हर परिस्थिति में धर्म का स्मरण कराया। यहां तक कि जब महाभारत युद्ध से पूर्व उन्होंने कर्ण को उसका सत्य बताया, तब भी उन्होंने उससे यही कहा कि युद्ध में वह धर्म का साथ दे, भले ही उसका निर्णय उनके लिए पीड़ादायक हो।

महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। असंख्य योद्धा मारे गए, कुरुवंश उजड़ गया और विजय के बाद भी पांडवों के जीवन में आनंद नहीं, बल्कि एक गहरा शून्य था। युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर के राजा बने, तब माता कुंती राजमहल में रहीं। उन्होंने न केवल अपने पुत्रों और वधुओं का मार्गदर्शन किया, बल्कि धृतराष्ट्र और गांधारी की भी सेवा की। यह वही गांधारी थीं, जिनके सौ पुत्र युद्ध में मारे गए थे। इसके बावजूद कुंती ने कभी उनके प्रति द्वेष नहीं रखा। उनके लिए सेवा भी एक साधना थी और पीड़ित के प्रति करुणा धर्म का अनिवार्य अंग।

समय बीतने के साथ माता कुंती के मन में संसार के प्रति वैराग्य और गहरा होता गया। जिन पुत्रों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया था, वे अब सुरक्षित और सत्तासीन थे। उनके कर्तव्य पूर्ण हो चुके थे। राजमहल का वैभव, सत्ता का आकर्षण और सांसारिक संबंध अब उन्हें बांध नहीं पा रहे थे। इसी समय धृतराष्ट्र और गांधारी ने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने का निर्णय लिया। यह निर्णय केवल वन जाने का नहीं था, बल्कि संसार से धीरे-धीरे विरक्त होकर आत्मा की अंतिम यात्रा की तैयारी का था। कुंती ने भी उनके साथ वन जाने का निर्णय लिया। यह निर्णय इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने मोह के अंतिम बंधन को भी स्वयं ही काट दिया।

वन में कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी का जीवन अत्यंत कठोर था। वे तपस्या, संयम और आत्मचिंतन में लीन रहते थे। राजसी जीवन से आए इन तीनों ने साधुओं जैसा जीवन अपनाया। कुंती के लिए यह जीवन नया नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा पहले ही कष्टों में बिताया था। वनवास उनके लिए बाहरी परिवर्तन था, आंतरिक नहीं। वहां वे अपने अतीत पर नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि पर केंद्रित थीं।

माता कुंती की मृत्यु महाभारत की सबसे करुण और साथ ही सबसे आध्यात्मिक घटनाओं में से एक मानी जाती है। एक दिन वन में अचानक भीषण अग्नि फैल गई। कहा जाता है कि उस समय कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें अपने शरीर की सुध ही नहीं रही। वे न भागे, न बचने का प्रयास किया। अग्नि ने उनके नश्वर शरीर को भस्म कर दिया। यह मृत्यु सामान्य नहीं थी, बल्कि योगाग्नि और वैराग्य की चरम अवस्था का प्रतीक थी। शास्त्रों में माना जाता है कि ऐसी मृत्यु मोक्षदायी होती है।

धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती—तीनों को इस अग्नि में देह त्याग के साथ मोक्ष की प्राप्ति हुई। माता कुंती के लिए यह अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा की पूर्णता थी। माना जाता है कि मृत्यु के बाद श्रीकृष्ण ने स्वयं माता कुंती को अपने धाम में स्थान दिया। यह उसी कुंती के लिए था, जिसने जीवन भर कृष्ण को केवल देवता नहीं, बल्कि सखा और मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया था। कुंती का प्रसिद्ध स्तुति प्रसंग, जिसमें वे कृष्ण से दुःख मांगती हैं ताकि उन्हें ईश्वर का स्मरण बना रहे, उनकी उच्चतम आध्यात्मिक चेतना को दर्शाता है।

माता कुंती की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुख, संघर्ष और त्याग कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के साधन हैं। उन्होंने कभी अपने कष्टों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें धर्म की कसौटी बना दिया। उनका जीवन यह भी सिखाता है कि मातृत्व केवल प्रेम नहीं, बल्कि सही दिशा देने का साहस भी है। और अंततः, उनका अंत यह संदेश देता है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्यों से मुक्त होकर मोह का त्याग कर देता है, तब मृत्यु भी भयावह नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार बन जाती है। माता कुंती का जीवन और उनकी दर्दनाक किंतु दिव्य मृत्यु आज भी यह प्रश्न छोड़ जाती है कि क्या हम अपने जीवन में कभी उस स्तर तक वैराग्य, करुणा और धर्म को स्थान दे पाएंगे। उनका उत्तर शायद यही है कि मोक्ष किसी एक क्षण में नहीं, बल्कि पूरे जीवन की साधना में छिपा होता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

उप मुख्यमंत्री श्री हर्षभाई संघवी ने राजकोट में सौराष्ट्र कच्छ के अग्रणी उद्योगपतियों के साथ संवाद किया

(जीएनएस)। गांधीनगर : उप मुख्यमंत्री श्री हर्षभाई संघवी ने सोमवार को राजकोट में सौराष्ट्र-कच्छ के अग्रणी उद्योगपतियों के साथ संवाद किया। जिसमें उन्होंने विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव उद्योगों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उद्योगकारों का आह्वान किया कि वे वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए राज्य में अपना निवेश बढ़ाएं और गुजरात के विकास को नए पंख दें। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने 10,435 उद्यमियों को 956.51 करोड़ रुपए की प्रोत्साहक सहायता का वितरण करने के साथ ही उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 137 उद्योगों को 671 करोड़ रुपए से अधिक के स्वीकृति पत्र वितरित किए।

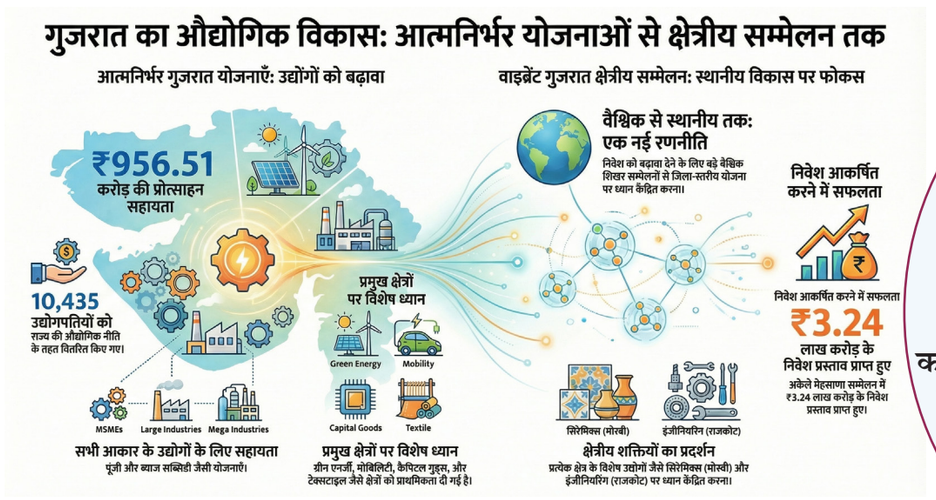

▸▸ उप मुख्यमंत्री श्री हर्षभाई संघवी ने उद्योगकारों से वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा का आह्वान किया

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव उद्योगों के साथ खड़ी है : श्री हर्षभाई संघवी

▸▸ उप मुख्यमंत्री ने 10,435 उद्यमियों को 956.51 करोड़ रुपए की प्रोत्साहक सहायता और 137 उद्योगकारों को 671 करोड़ रुपए से अधिक के स्वीकृति पत्रों का वितरण किया

▸▸ वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस सौराष्ट्र-कच्छ के उद्योग जगत के लिए नए युग का प्रवेश द्वार बनेगी : प्रभारी मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

राजकोट जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में श्री हर्षभाई संघवी ने उद्योगकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के उद्योगकार साहस और निवेश करके हजारों-लाखों युवाओं के सपने साकार कर रहे हैं, तब राज्य सरकार भी उद्योगकारों की समस्याओं को हल करते हुए एक विशिष्ट दृष्टिकोण के साथ प्रयासरत है, जिससे कि वे आसानी से निवेश और उत्पादन करके अपने उद्योगों का विकास कर सकें।

उन्होंने कहा कि राजकोट गुजरात का ग्रोथ इंजन है। वर्तमान में राजकोट निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में रॉकेट की गति से उड़ रहा है। आगामी दिनों में राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है और 11 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस से राजकोट और सौराष्ट्र-कच्छ के उद्योगों को बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म और बूस्ट मिलेगा।

छोटे उद्योगों के विकास के लिए सरकार किए जा रहे सरकार के उपायों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) का विकास में अहम योगदान होता है। इसलिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार इस सेक्टर को बूस्ट करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए प्रशासनिक और कागजी प्रक्रियाओं को आसान बनाकर उद्योगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने उद्योगों के हित के लिए राज्य के उद्योग विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि पहले रोजाना लगभग 225 उद्योगपतियों को सब्सिडी दी जाती थी, अब रोजाना 450 सब्सिडी मंजूर की जा रही हैं और आने वाले दिनों में रोजाना 700 सब्सिडी को मंजूर करने का लक्ष्य है।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य के राजस्व विभाग ने देश में पहली बार काफी कम समय में राज्य में 16 से अधिक जीआईडीसी (औद्योगिक क्षेत्र) के लिए स्थान की पहचान कर उसे आवंटित करने का काम किया है, जो प्रशंसनीय है।

बैठक का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि उद्योगकारों को अपनी समस्याओं या मुद्दों को लेकर गांधीनगर तक आना न पड़े और उनकी छोटी-बड़ी समस्याओं का तत्काल निपटारा किया जा सके, इसके लिए सरकार विभिन्न विभागों के साथ आपके द्वार पर आई है। उन्होंने उद्योगपतियों को विश्वास दिलाया कि जब वे राज्य के लाखों युवाओं को रोजगार प्रदान कर उनके सपने साकार कर रहे हैं, तब मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार एक सहयोगी के रूप में आपके साथ खड़ी है।

इस अवसर पर जीतूभाई वाघाणी ने अपने संबोधन में कहा कि राजकोट राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण औद्योगिक गढ़ है। स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि उद्योग जगत की छोटे-बड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री और सरकार के समक्ष लगातार पूरी जागरूकता के साथ मुद्दे उठाते हैं, जिससे राजकोट की विकास यात्रा को तेजी मिल रही है।

प्रभारी मंत्री ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्षभाई संघवी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शायद यह पहली ऐसी घटना है, जब समूचा उद्योग विभाग, उसके उच्च सचिव और सभी वरिष्ठ अधिकारीगण राजकोट

सहित सौराष्ट्र एवं कच्छ के उद्योगपतियों की समस्याओं को रूबरू सुनने और स्थल पर ही निराकरण लाने के लिए उपस्थित हैं। यह उद्योगों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य में तेज गति से हो रहे विकास का उल्लेख करते हुए श्री वाघाणी ने कहा कि सौराष्ट्र और कच्छ में आयोजित होने जा रही यह वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस उद्योग जगत के लिए नए युग का प्रवेश द्वार साबित होगी। जिला स्तर पर आयोजित कार्यशाला और कॉन्फ्रेंस के कारण करोड़ों रुपए के एमओयू हो रहे हैं।

प्रभारी मंत्री ने उद्योगपतियों और व्यापारियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उद्योग जगत की दिक्कतों का स्थायी और उचित समाधान करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

उद्योग एवं खान विभाग की अपर मुख्य सचिव सुश्री ममता वर्मा ने स्वागत भाषण में कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की जबकि राजकोट जिला कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश ने आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रवीणाबेन रंगाणी, सांसद श्री केसकरीदेव सिंह झाला, विधायक सर्वश्री उदयभाई कानगड़, रमेशभाई टीलाळा, डॉ. महेन्द्रभाई पाडलिया, श्रीमती भानुबेन बाबरिया, डॉ. दर्शिताबेन शाह, दुर्लभजीभाई देथरिया, पूर्व सांसद श्री रमेशभाई धडुक, श्री माधवभाई दवे सहित कई अग्रणी, राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि, उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप, रेंज आईजी श्री अशोक यादव, एमएसएमई आयुक्त श्री संदीप सागले, भूविज्ञान और खनन आयुक्त, जीआईडीसी की प्रबंध निदेशक सुश्री प्रवीणा डी.के., सेटलमेंट कमिश्नर श्री बिजल शाह, मनपा आयुक्त श्री तुषार सुमेरा, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) आयुक्त, औद्योगिक विस्तार-ब्यूरो (इंडेक्स-बी) के एमडी श्री के.सी. संपत, जिला कलेक्टर डॉ. ओमप्रकाश, जिला विकास अधिकारी श्री अनंदु सुरेश गोविंद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और सौराष्ट्र एवं कच्छ के अग्रणी उद्योगकार बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

कांदिवली–बोरीवली सेक्शन में 6वीं लाइन के कार्य के संबंध में पश्चिम रेलवे का मेजर ब्लॉक

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली–बोरीवली सेक्शन के बीच छठी लाइन के निर्माण कार्य के संबंध में 20/21 दिसम्बर, 2025 की रात्रि से 18 जनवरी, 2026 तक कुल 30 दिनों का ब्लॉक लिया जा रहा है। इस ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेन सेवाएँ प्रभावित रहेंगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 06/07 जनवरी, 2026 की रात्रि में कांदिवली पर अप फास्ट लाइन पर प्वाइंट संख्या 103 के इन्सर्शन हेतु एक मेजर ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक अप फास्ट लाइन पर 00:00 बजे से 05:30 बजे तक तथा डाउन फास्ट लाइन पर 01:00 बजे से 04:30 बजे तक रहेगा।

उपर्युक्त ब्लॉकों एवं 5वीं लाइन के निलंबन के कारण कुछ उपनगरीय ट्रेन सेवाएँ निरस्त रहेंगी, जबकि कुछ मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को रेगुलेट किया जाएगा। इस ब्लॉक के कारण प्रभावित ट्रेनों की विस्तृत सूची अनुलग्नक–I एवं II में दी गई है।

पश्चिम रेलवे ने अप्रैल से दिसम्बर, 2025 के दौरान गहन टिकट जांच अभियानों से प्राप्त किया 155 करोड़ से अधिक का जुर्माना

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे पर निर्बाध, आरामदायक यात्रा एवं बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी बोनाफाइड यात्रियों को मुंबई उपनगरीय, मेल/एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेनों तथा हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों में निरंतर सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि बिना टिकट/अनियमित यात्रा की समस्या पर अंकुश लगाया जा सके। पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारियों की निगरानी में कार्यरत हाई मोटिवेटेड टिकट चेकिंग टीम द्वारा अप्रैल से दिसम्बर 2025 की अवधि के दौरान अनेक टिकट चेकिंग अभियान आयोजित किए गए। इसके परिणामस्वरूप 155.46 करोड़ की राशि की वसूली की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 49% अधिक है। इस राशि में मुंबई उपनगरीय खंड से 41.26 करोड़ की वसूली भी शामिल है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केवल दिसम्बर माह में ही बिना टिकट/अनियमित यात्रियों, जिनमें बिना बुक किए गए सामान के मामले भी शामिल हैं, 2.51 लाख मामलों की पहचान के

माध्यम से 15.54 करोड़ की राशि वसूल की गई, जो पिछले वर्ष के दिसम्बर माह की तुलना में लगभग 42% अधिक है। इसके अलावा, दिसम्बर 2025 के दौरान पश्चिम रेलवे ने 92 हजार मामलों की पहचान के माध्यम से 3.95 करोड़ की जुर्माना राशि प्राप्त की। एसी लोकल ट्रेनों में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए नियमित रूप से औचक टिकट चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। एसी लोकल ट्रेनों में केंद्रित टिकट चेकिंग अभियानों के परिणामस्वरूप अप्रैल से दिसम्बर 2025 की अवधि के दौरान लगभग 91 हजार अनधिकृत यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया तथा 2.97 करोड़ की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 97% अधिक है। इस प्रकार के उल्लेखनीय परिणाम अनधिकृत यात्रा पर अंकुश लगाने, यात्री अनुभव को बेहतर बनाने तथा सार्वजनिक राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति पश्चिम रेलवे की प्रतिबद्धता एवं समर्पण को दर्शाते हैं। पश्चिम रेलवे आम जनता से अपील करती है कि कृपया उचित एवं वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें।

अहमदाबाद मंडल ने रेलवे परिसर में थूकने एवं गंदगी फैलाने वाले यात्रियों/लोगों के विरुद्ध की सख्त कार्रवाई

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 198 के अंतर्गत रेल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने एवं यात्रियों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 के दौरान सघन अभियान चलाया गया।

इस अभियान के तहत रेलवे परिसर में थूकने एवं गंदगी फैलाने वाले लोगों पर कार्यवाही करते हुए वर्ष 2025-26 में अभी तक कुल 2330 मामलों में कार्रवाई की गई, जिनसे 5,05,707/- का जुर्माना वसूला गया। दिसंबर 2025 के दौरान ही 250 मामलों में कार्रवाई करते हुए 59,100/- का जुर्माना वसूल किया गया। रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि रेलवे परिसर एवं ट्रेनों में गंदगी न फैलाएं तथा स्वच्छता नियमों का पालन करें। स्वच्छ रेलवे, सुरक्षित रेलवे के निर्माण में सभी का सहयोग आवश्यक है।

रुपये में होगा भारत–इज़राइल व्यापार, एसबीआई बनेगा सेतु, वैश्विक वित्त में भारत की नई मुद्रा पहल

(जीएनएस)। यरुशलम। भारत और इज़राइल के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को एक नई दिशा देने की तैयारी तेज हो गई है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को अब भारतीय रुपये में निपटाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। यह पहल न केवल प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते की पृष्ठभूमि में अहम है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारतीय रुपये के उपयोग और स्वीकार्यता को बढ़ाने की भारत सरकार की व्यापक रणनीति का भी हिस्सा है। इज़राइल में कार्यरत एकमात्र भारतीय बैंक के रूप में एसबीआई इस नई व्यवस्था की धुरी बनकर उभर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्यात–आयात से जुड़े लेनदेन को रुपये में निपटाने की प्रक्रिया को अमल में लाने की तैयारी की जा रही है। एसबीआई इज़राइल के मुख्य

कार्यपालक अधिकारी वी. मणिवन्नन के अनुसार, यह पहल भारत की उस नीति के अनुरूप है, जिसके तहत मित्र और साझेदार देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम की जा सके।

इस व्यवस्था के तहत 'स्पेशल रुपया वोस्ट्रो अकाउंट' प्रणाली के माध्यम से इज़राइली कंपनियों को यह सुविधा मिलेगी कि वे भारत के साथ होने वाले व्यापारिक लेनदेन सीधे रुपये में कर सकें। भुगतान और प्राप्ति दोनों ही रुपये में होने से विदेशी मुद्रा विनिमय से जुड़े जोखिमों में कमी आएगी। साथ ही लेनदेन की लागत घटेगी, प्रक्रिया तेज होगी और व्यापारियों को अधिक पारदर्शिता मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार को नई गति मिलेगी और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए भी सीमा पार व्यापार अधिक सहज बन सकेगा।

वर्ष 2007 से इज़राइल में मौजूद एसबीआई ने वैश्विक महामारी, भू-राजनीतिक तनाव और क्षेत्रीय अस्थिरता के बावजूद अपने परिचालन को लगातार बनाए रखा है। वर्तमान में वह इज़राइल में एकमात्र भारतीय बैंक है, जो भारतीय कंपनियों और निवेशकों के लिए वित्तीय सेतु का काम कर रहा है। अब रुपये में व्यापार की व्यवस्था लागू होने से एसबीआई की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि यही बैंक इस नई भुगतान प्रणाली के क्रियान्वयन, अनुपालन और सुचारु संचालन का केंद्र बनेगा।

यह पहल ऐसे समय पर सामने आई है, जब भारत और इज़राइल आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों को खोलने पर जोर दे रहे हैं। हाल के महीनों में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई यात्राओं और बैठकों ने व्यापार, निवेश, रक्षा, तकनीक और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊर्जा दी है। इसी पृष्ठभूमि में रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की यह पहल भविष्य की साझेदारी के लिए मजबूत आधार तैयार करती दिख रही है।

आर्थिक जानकारों का मानना है कि यदि यह व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू होती है, तो यह न केवल भारत–इज़राइल संबंधों को नई ऊंचाई देगी, बल्कि अन्य देशों के साथ भी स्थानीय मुद्रा में व्यापार को प्रोत्साहित करने के भारत के प्रयासों को बल मिलेगा। इस तरह भारतीय रुपये का अंतरराष्ट्रीय उपयोग बढ़ेगा और भारत वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाएगा।

सोना वायदा में 1994 रुपये और चांदी वायदा में 7283 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा 47 रुपये बढ़ा

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 138118.31 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 37662.66 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 100430.71 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 35730 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2115.13 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 31337.63 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 136300 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 138200 रुपये और नीचे में 136300 रुपये पर पहुंचकर, 135761 रुपये के पिछले बंद के सामने 1994 रुपये या 1.47 फीसदी की तेजी के संग 137755 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा 810 रुपये या 0.72 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 112830 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 112 रुपये या 0.8 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 14107 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी जनवरी वायदा 135590 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 137497 रुपये और नीचे में 133864 रुपये पर पहुंचकर, 1998 रुपये या 1.5 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 135495 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 138340 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 138787 रुपये और नीचे में 137502 रुपये पर पहुंचकर, 136777 रुपये के पिछले बंद के सामने 1573 रुपये या 1.15 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 138350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 244000 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 249900 रुपये और नीचे में 241223 रुपये पर पहुंचकर, 236316 रुपये के पिछले बंद के सामने 7283 रुपये या 3.08 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 243599 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 6778 रुपये या 2.84 फीसदी बढ़कर 245563 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 6714 रुपये या 2.81 फीसदी की बढ़त के साथ 245561 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 37662.66 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 100430.71 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 31337.63 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 35730 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 3972.00 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा 16.9 रुपये या 1.31 फीसदी बढ़कर 1304 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता जनवरी वायदा 2.65 रुपये या 0.86 फीसदी की मजबूती के साथ 309.25 रुपये प्रति किलो बोला गया। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 2.05 रुपये या 0.68 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 304.8 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा 1.2 रुपये या 0.66 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 184.1 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2432.55 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा 5175 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5206 रुपये और नीचे में 5101 रुपये पर पहुंचकर, 47 रुपये या 0.91 फीसदी बढ़कर 5202 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 45 रुपये या 0.87 फीसदी की मजबूती के साथ 5202 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा 327.6 रुपये पर ऊपर में 327.6 रुपये और नीचे में 311.6 रुपये पर पहुंचकर, 332.8 रुपये के पिछले बंद के सामने 16.5 रुपये या 4.96 फीसदी औंधकर 316.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 16.8 रुपये या 5.05 फीसदी लुढ़ककर 316.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 1017.7 रुपये के भाव पर खूलकर, 31.4 रुपये या 3.01 फीसदी गिरकर 1010.5 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 16216.36 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 15121.27 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3368.47 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 326.56 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 33.97 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 240.34 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 642.17 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1779.98 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 7.43 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.26 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 19012 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 73446 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 27746 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 414453 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 45316 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 16940 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 40061 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 103902 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 21768 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 42507 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा 35650 पॉइंट पर खूलकर, 36026 के उच्च और 35351 के नीचले स्तर को छूकर, 558 पॉइंट बढ़कर 35730 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 15.9 रुपये की बढ़त के साथ 110.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 10.45 रुपये की गिरावट के साथ 20.05 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 526.5 रुपये की बढ़त के साथ 1850 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 260000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1730.5 रुपये की बढ़त के साथ 9004 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.87 रुपये की बढ़त के साथ 62.99 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.18 रुपये की बढ़त के साथ 11.7 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 31.7 रुपये की गिरावट के साथ 111.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 4.6 रुपये की बढ़त के साथ 18.05 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 130000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 340 रुपये की गिरावट के साथ 498 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 190000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 148 रुपये की गिरावट के साथ 1032.5 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 7.22 रुपये की गिरावट के साथ 13.39 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.59 रुपये की गिरावट के साथ 6.1 रुपये हुआ।

भारत के कुल सिरेमिक निर्यात में 90% हिस्सेदारी के साथ मोरबी बना भारत की 'सिरेमिक राजधानी'

▸▸ वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) कच्छ सौराष्ट्र में मोरबी सिरेमिक क्लस्टर को विशेष जोन के रूप में पेश किया जाएगा

▸▸ 9 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार देता है मोरबी का सिरेमिक उद्योग

▸▸ पॉलीपैक इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में भी मोरबी बन सकता है गुजरात का अग्रणी जिला

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में गुजरात वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) कच्छ-सौराष्ट्र के दूसरे संस्करण के लिए तैयार हो रहा है। 11 एवं 12 जनवरी, 2026 के दौरान राजकोट में होने वाली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस कच्छ एवं सौराष्ट्र के हिस्से के रूप में राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सिरेमिक उद्योग का अगुवा, गुजरात का मोरबी जिला आज भारत की सिरेमिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ बन गया है। गुजरात के कुल सिरेमिक उत्पादन में अकेले लगभग 90 फीसदी हिस्सेदारी के साथ मोरबी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिरेमिक उत्पादन केंद्र है।

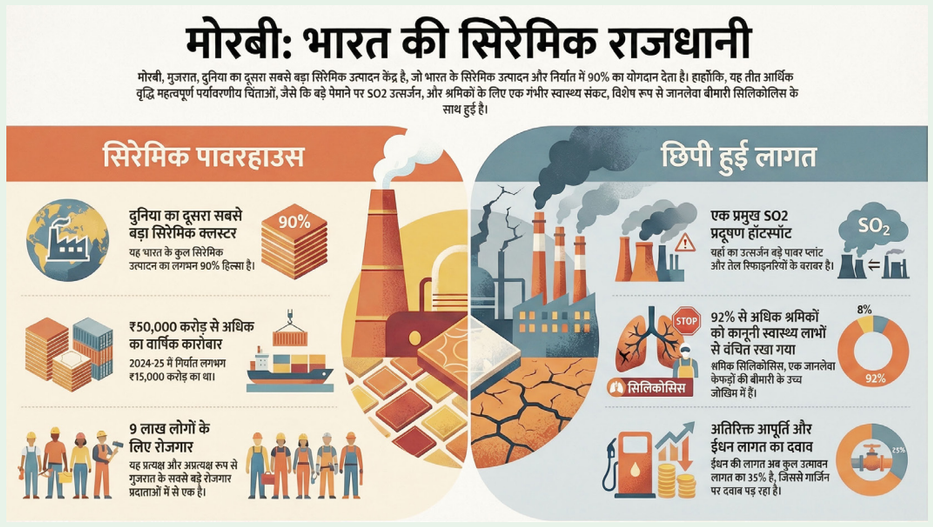

कुम्हार के चाक से वैश्विक सिरेमिक हब तक : मोरबी की उद्योग गाथा

मोरबी आज देश और दुनिया में सिरेमिक उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। शुरुआत में यहां पारंपरिक तरीके से मिट्टी के मटके, दीये, खपरैल और घरेलू मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। स्थानीय मिट्टी की गुणवत्ता और कारीगरों की कुशलता ने मोरबी के उत्पादों को एक नई पहचान दी। बाद में, वॉल क्लॉक (दीवार घड़ी) उद्योग की शुरुआत हुई। समय के साथ-साथ, 1970-80 के दशक में रूफ टाइल्स और ग्लेज्ड टाइल्स का उत्पादन शुरू हुआ और धीरे-धीरे मोरबी आधुनिक सिरेमिक उद्योग की दिशा में आगे बढ़ा। नई टेक्नोलॉजी, उन्नत मशीनरी और उद्यमिता के दृष्टिकोण ने इस शहर को सिरेमिक उद्योग के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान दी। आज मोरबी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और विट्रिफाइड टाइल्स के उत्पादन के लिए वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। मोरबी का सिरेमिक सफर परंपरा से प्रगति की ओर बढ़ने का बेजोड़ उदाहरण बन गया है।

गुजरात का मोरबी जिला बना भारत का सिरेमिक हब

इस वर्ष राजकोट में आयोजित होने वाली दूसरी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) कच्छ-सौराष्ट्र में मोरबी के सिरेमिक क्लस्टर की एक विशेष प्रदर्शनी होगी, जिसमें 'अद्यतन सिरेमिक्स', 'वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स', 'एनर्जी-एफिशिएंट टेक्नोलॉजी' और नए 'सिरेमिक पार्क' की प्रगति मुख्य आकर्षण होंगे। राज्य सरकार उद्योगों के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ऑटोमेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट रिसाइकिलिंग और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। मोरबी के उद्यमियों के परिश्रम, सरकार की प्रभावी नीतियों और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता के कारण आज मोरबी भारत की 'सिरेमिक राजधानी' बन गया है।

गत दो वर्षों के दौरान लाभार्थियों को मिला विभिन्न सरकारी सहायता योजना का लाभ

मोरबी जिले में गत दो वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी सहायता योजनाओं के तहत व्यापक और प्रभावी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जो जिले के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम सिद्ध हो रही है। राज्य सरकार की विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान लगभग 2200 से अधिक लाभार्थियों को सीधे 115 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता पहुंचाई गई है। इस सहायता से मोरबी जिले के नागरिकों को स्वरोजगार, उद्योग, जीवन स्तर में सुधार और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने के नए अवसर मिले हैं, जो राज्य सरकार की जनकल्याण की प्रतिबद्धता और सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है।

मोरबी का सिरेमिक उद्योग लगभग 9 लाख लोगों को देता है रोजगार

मोरबी जिले का सिरेमिक क्लस्टर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिरेमिक उत्पादों का उत्पादन करने वाला क्लस्टर है। मोरबी जिले में लगभग 1200 सिरेमिक इकाइयां हैं, जिनका कुल सालाना उत्पादन लगभग 60 लाख टन है। ये इकाइयां करीब 9 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती हैं।

भारत के कुल सिरेमिक निर्यात में लगभग 80 से 90 फीसदी का योगदान

मोरबी का सिरेमिक उद्योग वैश्विक बाजार में गुजरात तथा भारत की मजबूत पहचान बन रहा है। अनुमान के मुताबिक वर्ष 2024-25 के दौरान मोरबी से लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। खास बात यह है कि अकेला मोरबी भारत के कुल सिरेमिक निर्यात में 80 से 90 फीसदी का योगदान देता है। यहां बनाए जाने वाले उच्च गुणवत्ता के सिरेमिक टाइल्स और संबंधित उत्पादों को मुख्य रूप से अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ओमान और श्रीलंका जैसे देशों में निर्यात किया जाता है, जो मोरबी की वैश्विक विश्वसनीयता और 'मेड इन इंडिया-मेड इन गुजरात' ब्रांड की मजबूत स्थिति को साफ तौर पर उजागर करता है।

भारत के वॉल क्लॉक उत्पादन में मोरबी जिले की बड़ी हिस्सेदारी

सिरेमिक तथा पॉलीपैक के जैसे ही वॉल क्लॉक और गिफ्ट आर्टिकल उद्योग भी मोरबी में बड़े पैमाने पर विकसित हुआ है। भारत के वॉल क्लॉक उत्पादन में मोरबी जिले के वॉल क्लॉक तथा गिफ्ट आर्टिकल उद्योग की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। मोरबी जिले में वॉल क्लॉक की लगभग 150 से 200 इकाइयां हैं। ये उद्योग करीब 10 से 12 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार प्रदान करते हैं, जिनमें से 60 फीसदी महिलाएं हैं।

पॉलीपैक उद्योग के क्षेत्र में भी मोरबी बन सकता है राज्य का अग्रणी जिला

गुजरात का मोरबी जिला सिरामिक क्षेत्र की तरह ही पॉलीपैक उद्योग के क्षेत्र में भी निकट भविष्य में राज्य का एक अग्रणी जिला बन सकता है। अभी मोरबी जिले में पीपी (पॉलीप्रोपाइलिन) वूवन प्रोडक्ट की कुल 150 इकाइयां कार्यरत हैं। मोरबी का पॉलीपैक उद्योग अभी सालाना लगभग 5 लाख मीट्रिक टन पीपी वूवन फैब्रिक का उत्पादन करता है, जिसका कुल सालाना टर्नओवर लगभग 5500 करोड़ रुपए है। पॉलीपैक उद्योग आज मोरबी के लगभग 25 से 20 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है।

मासूम जिज्ञासा बनी मौत का कारण, कनेर का फल खाने से तीन नन्ही जिंदगियां बुझीं

(जीएनएस)। वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र अंतर्गत करधना गांव में सोमवार को जो हुआ, उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। हंसी-खेल से भरा दोपहर का समय कुछ ही पलों में चीख-पुकार और मातम में बदल गया। गांव के एक बगीचे में खेल रही तीन मासूम बच्चियों ने अनजाने में कनेर के जहरीले फल खा लिए और देखते-ही-देखते उनकी हालत बिगड़ती चली गई। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय परिजनों को उम्मीद थी कि शायद बच्चियों को बचा लिया जाएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इलाज के दौरान तीनों नन्ही जिंदगियां हमेशा के लिए बुझ गईं। करधना गांव निवासी मिथिलेश की बेटियां हर्षिता (6 वर्ष) और अंशिका (3 वर्ष) तथा मनीष की बेटी नैंसी (4 वर्ष) सोमवार दोपहर घर के पास स्थित बगीचे में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थीं। गर्मी के दिन थे और बच्चे पेड़ों की छांव में खेलते हुए समय बिता रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर बगीचे में लगे कनेर के पेड़ पर पड़ी, जिस पर लाल-गुलाबी फूलों के साथ फल भी लगे हुए थे। मासूम बच्चियों को न तो इस पौधे की विषाक्तता का ज्ञान था और न ही

यह अंदाजा कि देखने में सुंदर यह पेड़ मौत का कारण बन सकता है। खेल-खेल में वे कनेर के फल तोड़कर खाने लगीं। कुछ ही समय बीता था कि बच्चियों को बेचैनी होने लगी। पहले उल्टियां शुरू हुईं, फिर उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। बच्चियों की हालत देखकर आसपास मौजूद लोग और परिजन घबरा गए। जब तक वे कुछ समझ पाते, तब तक बच्चियों की हालत गंभीर हो चुकी थी। परिजन तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। रास्ते भर मां-बाप की आंखों में डर और उम्मीद एक साथ थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन जहर का असर इतना तेज था कि सभी प्रयास नाकाम साबित हुए। कुछ ही देर में एक-एक कर तीनों बच्चियों ने दम तोड़ दिया। बच्चियों की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे करधना गांव में कोहराम मच गया। जिन आंगनों में थोड़ी देर पहले बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं, वहां अब मातम और सिसकियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। मां-बाप बेसुध हो गए, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की आंखें नम हो गईं। हर कोई यही कहता नजर आया कि काश किसी को पहले पता होता कि कनेर का फल इतना खतरनाक है, तो शायद यह हादसा टल सकता था।

घटना की सूचना ग्राम प्रधान द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मिर्जामुराद थाना पुलिस और एडीसीपी वैभव बांगर मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से घटना की जानकारी ली और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में कनेर के जहरीले फल खाने से मौत की आशंका जताई गई है। पुलिस ने तीनों बच्चियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि मौत के कारणों की विधिवत पुष्टि की जा सके। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में गहरा शोक फैला दिया है। गांव के लोग स्तब्ध हैं और हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर मासूम बच्चों को ऐसी खतरनाक चीजों से कैसे बचाया जाए। जानकारों का कहना है कि कनेर का पौधा बेहद विषैला होता है और इसके पत्ते, फूल और फल सभी जहरीले होते हैं। बच्चों की जिज्ञासा और जानकारी की कमी कई बार ऐसे दर्दनाक हादसों को जन्म दे देती है।

करधना गांव में देर शाम तक सन्नाटा पसरा रहा। तीन घरों में एक साथ चूल्हा नहीं जला, हर तरफ सिर्फ रोने-बिलखने की आवाजें सुनाई देती रहीं। यह हादसा न सिर्फ तीन परिवारों के लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए ऐसा जख्म बन गया है, जिसे भरने में वक्त लगेगा। मासूमों की असमय मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है और एक कड़वा सच सामने रख दिया है कि छोटी-सी लापरवाही भी कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है।

रेलवे का सख्त फैसला, आधार से जुड़ी आईडी के बिना ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर पूरी तरह ब्रेक

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और आम यात्रियों के हित में बनाने के लिए एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। दलालों और फर्जी सॉफ्टवेयर के जरिए होने वाली धड़ल्ले से टिकट बुकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से अब आधार लिंकिंग को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत 12 जनवरी 2026 से ऐसे सभी IRCTC अकाउंट, जो आधार से लिंक और सत्यापित नहीं हैं, वे यात्रा से 60 दिन पहले खुलने वाली एडवांस रिजर्वेशन पीरियड की बुकिंग के दिन पूरे 24 घंटे ऑनलाइन टिकट नहीं खरीद सकेंगे। यह फैसला खासतौर पर उन लोकप्रिय ट्रेनों और रूट्स पर असर डालेगा, जहां टिकट खुलते ही कुछ ही मिनटों में सीटें फुल हो जाती हैं। रेलवे बोर्ड ने इस नियम को एक झटके में लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया, ताकि यात्रियों को अपना अकाउंट आधार से लिंक कराने का पर्याप्त समय मिल सके। 29 दिसंबर 2025 से बिना आधार लिंक वाले अकाउंट्स के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक बुकिंग पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद 5 जनवरी 2026 से इस समयसीमा को बढ़ाकर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया गया। अब अंतिम

चरण में 12 जनवरी 2026 से बिना आधार सत्यापन वाले अकाउंट्स पर पूरे दिन यानी सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस तीन-स्तरीय व्यवस्था का उद्देश्य यात्रियों को सचेत करना और उन्हें समय रहते आधार लिंकिंग के लिए प्रेरित करना है। रेलवे का मानना है कि इस फैसले से सबसे बड़ा फायदा आम और वास्तविक यात्रियों को होगा। त्योहारों, गर्मी की छुट्टियों और विशेष अवसरों पर अक्सर देखा जाता था कि दलाल और एजेंट फर्जी आईडी बनाकर चंद मिनटों में सैकड़ों टिकट बुक कर लेते थे, जिससे आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था। आधार सत्यापन लागू होने से एक व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित होगी और बल्क बुकिंग पर प्रभावी रोक लगेगी। रेलवे के शुरुआती आकलन के अनुसार, जब से यह व्यवस्था लागू की गई है, तब से आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावनाओं में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है।

आधार लिंक और वेरिफाइड अकाउंट रखने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेंगी। ऐसे यात्री एक महीने में 24 टिकट तक बुक कर सकेंगे, जबकि बिना आधार लिंक वाले अकाउंट्स के लिए यह सीमा 12 टिकट की ही रहेगी। इसके अलावा, तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान भी सत्यापित प्रोफाइल को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे वास्तविक जरूरतमंद यात्रियों को ज्यादा लाभ मिलेगा। सुरक्षा के लिहाज से भी यह कदम अहम है, क्योंकि आधार से जुड़े अकाउंट के जरिए कोई दूसरा व्यक्ति किसी के नाम पर टिकट बुक नहीं कर सकेगा।

रेलवे और आईआरसीटीसी की सख्ती का असर फर्जी आईडी पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अधिकारियों के मुताबिक जनवरी तक 3.3 करोड़ से अधिक फर्जी यूजर अकाउंट्स को रद्द किया जा चुका है, जबकि करीब 2.7 करोड़ संदिग्ध खातों की जांच चल रही है। इस तरह कुल मिलाकर लगभग छह करोड़ अकाउंट्स को सिस्टम से बाहर करने की तैयारी है। आधार सत्यापन और कड़े पहचान नियमों के चलते अब फर्जी आईडी बनाना लगभग नामुमकिन हो गया है। पहले जहां हर दिन करीब एक लाख नई यूजर आईडी बनती थीं, अब यह संख्या घटकर सिर्फ पांच हजार के आसपास रह गई है।

रेलवे का कहना है कि यह फैसला अस्थायी असुविधा के बजाय दीर्घकालिक सुधार की दिशा में उठाया गया कदम है। इससे न सिर्फ टिकट बुकिंग प्रणाली पारदर्शी होगी, बल्कि वर्षों से आम यात्रियों को परेशान करने वाले दलालों और अवैध सॉफ्टवेयर नेटवर्क पर भी निर्णायक चोट पड़ेगी। आने वाले दिनों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग का अनुभव अधिक भरोसेमंद और यात्रियों के अनुकूल होने की उम्मीद जताई जा रही है।

गोवा में आप को करारा राजनीतिक झटका, शीर्ष नेताओं के इस्तीफों से संगठन में उथल-पुथल

(जीएनएस)। पणजी। गोवा की राजनीति में आम आदमी पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा, जब पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर, कार्यवाहक राज्य प्रमुख श्रीकृष्ण परब और तीन अन्य प्रमुख पदाधिकारियों ने एक साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इन सामूहिक इस्तीफों ने न सिर्फ गोवा आप की आंतरिक स्थिति को उजागर कर दिया है, बल्कि आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लंबे समय से संगठनात्मक असंतोष और हालिया चुनावी हार से जूझ रही पार्टी के लिए यह घटनाक्रम एक बड़े संकट के रूप में देखा जा रहा है।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर ने अपने इस्तीफे की घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से की। उन्होंने लिखा कि वह आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और यह फैसला उन्होंने काफी सोच-विचार और साफ मन से लिया है। पालेकर ने अपने संदेश में कहा कि पद से अधिक सिद्धांत और सत्ता से अधिक मकसद उनके लिए मायने रखते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपने विश्वासों और गोवा के लोगों के साथ खड़े रहना चाहते हैं और उनका राजनीतिक सफर आगे भी जारी रहेगा। पालेकर के इस बयान को पार्टी नेतृत्व पर सीधा असंतोष और वैचारिक दूरी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अमित पालेकर, कार्यवाहक राज्य प्रमुख श्रीकृष्ण परब और गोवा आम आदमी पार्टी के युवा विंग अध्यक्ष रोहन नाइक ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस्तीफों की औपचारिक घोषणा की। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब हाल ही में हुए जिला परिषद चुनावों में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। दिसंबर 20 को हुए इन चुनावों में पार्टी ने 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे महज एक सीट पर ही जीत नसीब हुई। इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पार्टी नेतृत्व ने पालेकर को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया था, जिसे लेकर अंदरखाने असंतोष गहराता चला गया। गोवा आप के दो उपाध्यक्ष चेतन कामत और सरफराज ने भी पार्टी से इस्तीफा देने की पुष्टि की है, हालांकि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। इन इस्तीफों के साथ ही पार्टी का संगठनात्मक ढांचा कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम सिर्फ चुनावी हार का नतीजा नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही अंदरूनी खींचतान और निर्णय प्रक्रिया को लेकर असहमति का परिणाम है।

पत्रकारों से बातचीत में अमित पालेकर ने कहा कि पार्टी छोड़ने का फैसला उन्होंने अपने समर्थकों और फॉलोअर्स से सलाह लेने के बाद किया है। उन्होंने बताया कि उनके समर्थक चाहते थे कि उनकी राजनीति में स्पष्टता हो और वह किसी भ्रम की स्थिति में न रहें। पालेकर ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ उनका चार साल का सफर अब समाप्त हो गया है और उन्हें किसी तरह का पछतावा नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए वह सब कुछ किया, जो उनके स्तर पर संभव था।

गौरतलब है कि अमित पालेकर 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था। उस चुनाव में पार्टी ने 40 सदस्यीय विधानसभा में दो सीटें जीती थीं, जिसे आप ने गोवा में अपनी मौजूदगी के लिहाज से एक उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया था। हालांकि इसके बाद संगठन को मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने में पार्टी को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

कार्यवाहक राज्य प्रमुख श्रीकृष्ण परब ने अपने इस्तीफे को लेकर कहा कि वह पिछले महीने पालेकर को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के तरीके से असहमत थे। उन्होंने इसे पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ बताया और इसी असहमति को दर्ज कराने के लिए पद छोड़ने का फैसला किया। परब के इस बयान से साफ है कि नेतृत्व के फैसलों को लेकर पार्टी के अंदर गहरी नाराजगी थी।

इन इस्तीफों के बाद गोवा में आम आदमी पार्टी की स्थिति कमजोर होती दिख रही है। पार्टी नेतृत्व के सामने अब न सिर्फ संगठन को संभालने की चुनौती है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा हो गया है कि क्या आप गोवा में खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में बनाए रख पाएगी। राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को पार्टी के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, जो आने वाले दिनों में गोवा की सियासत में बड़े बदलाव का संकेत दे सकता है।

रेलवे ओवरब्रिज के शिलान्यास में बदला मंच, केंद्रीय मंत्री के सामने कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने, कुर्सियां उछलीं

(जीएनएस)। बंगलूरू। एक ओर विकास परियोजना का शिलान्यास और दूसरी ओर सियासी टकराव—कर्नाटक में रेलवे ओवरब्रिज के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान यही तस्वीर देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री वी. सोमन्ना की मौजूदगी में कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिससे कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। हालात इस कदर बिगड़े कि कुर्सियां उछलने लगीं और पुलिस को बीच में आकर स्थिति संभालनी पड़ी। कुछ देर के लिए पूरा कार्यक्रम सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए बैनरों से हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप था कि बैनरों में जानबूझकर जिला प्रभारी मंत्री शिवराज तंगड़गी और कोप्पल के सांसद राजशेखर हितनाल के नाम और तस्वीरें शामिल नहीं की गईं। कांग्रेस समर्थकों ने इसे न केवल अनदेखी बल्कि राज्य सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का अपमान करार दिया। केंद्रीय मंत्री वी. सोमन्ना के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही इस मुद्दे को लेकर विरोध तेज हो गया और बहस शुरू हो गई।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंच के पास नारेबाजी करते हुए सवाल उठाए कि जब परियोजना राज्य और केंद्र के सहयोग से बन रही है, तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज क्यों किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और देखते-ही-देखते दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। पहले जुबानी जंग चली, फिर धक्का-मुक्की शुरू हो गई और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। कुछ ही पलों में बात हाथापाई तक पहुंच गई।

स्थिति उस समय और बिगड़ गई, जब कार्यक्रम स्थल पर रखी कुर्सियां उछलने लगीं। मंच के पास मौजूद लोग इधर-उधर भागने लगे। पुलिसकर्मियों को तुरंत आगे आकर मोर्चा संभालना पड़ा। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को अलग-अलग करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ देर के लिए शिलान्यास कार्यक्रम पूरी तरह बाधित हो गया और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूत्रों के मुताबिक, हंगामे के दौरान केंद्रीय मंत्री वी. सोमन्ना द्वारा कांग्रेस समर्थकों के लिए कथित तौर पर "पतालम" शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिससे विवाद और भड़क गया। इस टिप्पणी से कांग्रेस कार्यकर्ता और अधिक नाराज हो गए और उन्होंने विरोध तेज कर दिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बयान को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि इस टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया।

काफी देर की तनातनी और पुलिस हस्तक्षेप के बाद हालात पर काबू पाया जा सका। इसके बावजूद कार्यक्रम को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया गया और केंद्रीय मंत्री ने शिलान्यास की रस्म पूरी की। इसके बाद वह कुछ देर रुकने के बाद वहां से रवाना हो गए। हालांकि मंत्री के जाने के बाद भी कार्यक्रम स्थल पर तनाव का माहौल बना रहा और कार्यकर्ता आपस में बहस करते नजर आए।

अधिकारियों के अनुसार, जिस रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास किया गया है, वह क्षेत्र के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इसके बनने से अंजनाद्री बेट्टा और प्रसिद्ध हुलिगेम्मा मंदिर तक पहुंच आसान होगी। श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों और व्यापारियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यातायात की समस्या से राहत मिलेगी।

लेकिन विकास से जुड़ी इस अहम परियोजना का शिलान्यास सियासी हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आया। जिस मंच से विकास की बात होनी थी, वहीं राजनीति हावी हो गई। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या विकास कार्यक्रमों को सियासी खींचतान से अलग रखा जा सकता है। फिलहाल इस शिलान्यास से ज्यादा चर्चा उस सियासी संग्राम की हो रही है, जिसने कुछ देर के लिए पूरे कार्यक्रम को शर्मसार कर दिया।

तीन घंटे में लखनऊ की तहज़ीब और तरक्की का सफर, 'लखनऊ दर्शन' बस सेवा से सैलानियों को मिलेगा नया अनुभव

(जीएनएस)। लखनऊ। नवाबी तहज़ीब, ऐतिहासिक इमारतों, हरे-भरे पार्कों और आधुनिक विकास की पहचान बने लखनऊ को अब पर्यटक एक ही यात्रा में नजदीक से देख और महसूस कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग 7 जनवरी से 'लखनऊ दर्शन' बस सेवा शुरू करने जा रहा है, जिसके जरिए राजधानी आने वाले सैलानियों को मात्र तीन घंटे में शहर के प्रमुख ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आधुनिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इस विशेष बस सेवा का शुभारंभ मंगलवार को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह 1090 चौराहे से हरी झंडी दिखाकर करेंगे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि लखनऊ दर्शन बस सेवा राजधानी की विशिष्ट पहचान को देश और दुनिया के सामने और मजबूती से प्रस्तुत करेगी। यह सेवा उन पर्यटकों के लिए बेहद उपयोगी होगी, जिनके पास सीमित समय होता है, लेकिन वे लखनऊ की पूरी झलक एक ही दिन में देखना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि इससे स्थानीय कारोबार, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सेवाओं को भी नई गति मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि पर्यटकों को एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक भ्रमण अनुभव मिले। यह बस सेवा प्रतिदिन सुबह और शाम दो पालियों में संचालित होगी। सुबह की पाली 8:30 बजे शुरू होकर 11:30 बजे तक चलेगी। यात्रा की शुरुआत 1090 चौराहे से होगी, जहां से बस राजभवन, जीपीओ और हजरतगंज के प्रमुख इलाकों से गुजरते हुए पर्यटकों को शहर की रौनक और औपनिवेशिक दौर की वास्तुकला से परिचित कराएगी। इसके बाद बस बेगम हजरत महल पार्क, ग्लोब पार्क और छतर मंजिल होते हुए ऐतिहासिक रेजीडेंसी परिसर पहुंचेगी, जहां 1857 की क्रांति से जुड़े इस महत्वपूर्ण स्थल पर करीब 40 मिनट का ठहराव रहेगा। रेजीडेंसी के बाद बस सिब्तैनाबाद इमामबाड़ा के मार्ग से होते हुए फिर हजरतगंज पहुंचेगी। यहां पर्यटकों को विधानसभा भवन का 40 मिनट का विशेष भ्रमण कराया जाएगा, जिससे वे प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और वास्तुकला को नजदीक से देख सकें। इसके पश्चात बस राजभवन और कैथेड्रल चर्च के रास्ते यूपी दर्शन पार्क पहुंचेगी, जहां 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद अंबेडकर पार्क और गोमती रिवर फ्रंट की खूबसूरती का आनंद लेते हुए यात्रा का समापन पुनः 1090 चौराहे पर होगा। इस टूर पैकेज में रेजीडेंसी और यूपी दर्शन पार्क के प्रवेश टिकट शामिल हैं, वहीं विधानसभा भवन में प्रवेश की विशेष व्यवस्था भी की गई है।

शाम की पाली में लखनऊ दर्शन बस सेवा 4 बजे से 7 बजे तक संचालित होगी। यह यात्रा भी 1090 चौराहे, गोमती नगर से शुरू होगी और सबसे पहले यूपी दर्शन पार्क पहुंचेगी, जहां पर्यटकों को 30 मिनट का भ्रमण कराया जाएगा। इसके बाद बस अंबेडकर पार्क, गोमती रिवर फ्रंट, कैथेड्रल चर्च और राजभवन से होते हुए विधानसभा भवन पहुंचेगी।